

दक्षिण भारत राष्ट्रमत



#मेराटैक्समेराअधिकार

श्री डी.के. शिवकुमार
माननीय उपमुख्यमंत्री

श्री सिद्धरामय्या
माननीय मुख्यमंत्री



कर्नाटक और कन्नड़िगाओं पर केंद्र सरकार के आर्थिक अत्याचार के खिलाफ

चलो दिल्ली

अनुदान देने में कर्नाटक के साथ हो रहा भेदभाव !
सुविधाओं के प्रावधान में कन्नड़िगाओं के साथ अन्याय !!

07 फरवरी 2024 को
सुबह 11.00 बजे

जंतर मंतर
नई दिल्ली

दिल्ली चलिए
सवाल कीजिए...

- सूखा राहत के लिए धन क्यों नहीं ?
राज्य की मांग: 18,177 करोड़ रुपए
केंद्र द्वारा जारी: शून्य
- विशेष अनुदान क्यों नहीं ?
15वें वित्त आयोग की सिफारिश: 5,495 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार द्वारा जारी: शून्य
- टैक्स हिस्सेदारी में भेदभाव क्यों ?
4.72 प्रतिशत से 3.64 प्रतिशत की कमी
राज्य को नुकसान: 62,098 करोड़ रुपए
(पांच वर्षों में)
- साझेदारी योजना के लिए अनुदान में कटौती क्यों ?
वर्ष 2021-22: 20,000 करोड़ रुपए
वर्ष 2022-23: 13,000 करोड़ रुपए
- भद्रा अपलैंड परियोजना की उपेक्षा
2023-24 में घोषणा : 5,300 करोड़ रुपए.
केंद्र सरकार द्वारा जारी : शून्य
- एक अधूरा सपना
एम्स एक सपना बना हुआ है
महादाई योजना को मान्यता नहीं है

केंद्र सरकार के अन्याय
के कारण 2017-18 से
कर्नाटक का नुकसान

रु. 1,87,000 करोड़

